कॉलेजों को सुधारना एकेटीयू के लिए सिरदर्द

जासं, लखनऊ : सूबे में धड़ल्ले से खुले प्रोफेशनल कॉलेजों के बावत एक बड़ा सच सामने आया है। ऊंची रसूख और मोटी आमदनी की लालसा रखने वाले कॉलेज प्रबंधतंत्र ने शैक्षिक संस्थान के संचालन की मूल अर्हता को भी पूरा करना उचित नहीं समझा। इसके चलते कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय (एकेटीयू) तक समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हद तो तब हो गई जब मानकों को पूरा करने संबंधी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के आदेशों को भी अधिकांश कॉलेजों ने अनदेखा कर दिया। आखिरकार अपनी साख बचाने के लिए विश्वविद्यालय को ही कॉलेज के सामने एड़ी रगड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

जी हां, एकेटीयू ने किसी भी अच्छे संस्थान के लिए आवश्यक आदर्श सेवा नियमावली को बनाया है। लेकिन, कॉलेजों के ओर से मॉडल बाईलाज, सेवा नियमावली नहीं बनाई गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने पूर्व में भी मॉडल बाईलाज, सेवा नियमावली के संबंध में सुझाव मांगे थे। पर किसी भी कॉलेज ने विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई सुझाव देने उचित नहीं समझा। आखिरकार कॉलेजों के रवैए से आजिज आकर एकेटीयू ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्थान की संबद्धता विस्तारण पर विचार करने के लिए संस्थान की आदर्श सेवा नियमावली, सेवा नियमावलियों को भी एक प्रमुख बिंदु बताते हुए सभी कॉलेजों को चेतावनी दे डाली। अब देखना यह है कॉलेजों का इस तरह का मनमाना रवैया क्या एकेटीयू सुधारने में सफल होगा।

अंधेरगर्दी

- नहीं बन पा रही आदर्श सेवा नियमावली, धड़ल्ले से चल रहे कॉलेज
- एकेटीयू के पत्राचार का किसी कॉलेज ने दिया नहीं दिया जबाव

क्या है आदर्श, सेवा नियमावली

आदर्श सेवा नियमावली का मकसद शिक्षकों के हित को बरकरार रखना एवं छात्रों के पठन पाठन पर किसी तरह का असर न पड़ना है। इसके तहत मुख्य रूप से शिक्षकों को शोषण से बचाना व उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है।

"आदर्श सेवा नियमावली को सभी कॉलेजों द्वारा बनाए जाने एवं उसके अनुपालन के लिए पत्राचार किया गया है। ऐसा न करने वाले कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

-प्रो. विनय कुमार पाठक, वीसी

प्राइवेट कॉलेजों ने बढ़ाई विश्वविद्यालय की मुश्किलें

जासं, लखनऊ : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय (एकेटीयू) इन दिनों अपने कॉलेजों से आजिज आ चुका है। कॉलेजों द्वारा उठाए गए अधिकांश मामलों में एकेटीयू को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रबंधतंत्र के उत्पीड़न के शिकार शिक्षकों ने कॉलेजों के विरुद्ध वाद दायर करने के साथ ही विश्वविद्यालय को भी पक्षकार बनाया लिया। अब मामले की जानकारी हुए बिना कोर्ट के समक्ष विश्वविद्यालय का पेश होना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

सूबे के अधिकांश संस्थानों में प्रशासकीय परिषद अथवा प्रबंधन बोर्ड निष्क्रिय हैं अथवा उसका गठन ही नहीं किया गया। इसके चलते संस्थानों में पारदर्शिता का अभाव है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में शिक्षकों के साथ उन कॉलेज प्रबंधन द्वारा मनमाना व्यवहार किया जाता होगा। ऐसे में काफी भुक्तभोगी शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर करने में विश्वविद्यालय को भी पक्षकार बनाया जाता है। कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को मामले से अवगत न कराया जाना विश्वविद्यालय को उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में मुसीबतें खड़ी कर रहा है। ऐसे में गंभीर हुए एकेटीयू प्रबंधन ने कॉलेज प्रबंधन से पत्राचार कर शिक्षकों पर कार्रवाइ किए जाने से पहले सभी मामलों को विवि के संज्ञान में लाए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

- प्रोफेशनल कॉलेजों की मनमानी से कोर्ट में बढ़ रहे वादों पर एकेटीयू गंभीर
- बिना संज्ञान में लाए शिक्षकों के विरुद्ध कदम उठाया तो होगी कार्रवाई

क्या कहते हैं कुलपति

प्रो.विनय कुमार पाठक का कहना है कि इस संदर्भ में कॉलेजों से पत्राचार कर उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। बिना संज्ञान में लाए शिक्षकों पर कार्रवाई करने वाले कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इंजीनियरिंग पास छात्र को कर दिया फेल

जासं, लखनऊ: इंदिरानगर निवासी सूरज प्रताप सिंह फैजाबाद रोड स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। सिविल ट्रेड में द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर अब तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद समाज कल्याण विभाग के शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन में अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने उसे फेल बता कर प्रार्थना पत्र फारवर्ड कर दिया। आर्थिक विपन्नता झेल रहे छात्र ने समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया तो ऐसी जानकारी पर उसके होश फाख्ता हो गए। उसने जिला समाज कल्याण अधिकारी और समाज कल्याण निदेशक को प्रार्थना पत्र देकर शुल्क प्रतिपूर्ति देने की मांग की है। सूरज का यह अकेला मामला नही है। एकेटीयू की लापरवाही के ऐसे सैकड़ों मामले प्रदेश स्तर पर हैं। उनकी लापरवाही के चलते गरीब छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

ऐसे जो भी मामले प्रकाश में आ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल की जा रही है। यदि विश्वविद्यालय की ओर से गड़बड़ी हुई है तो उसे सही कराया जाएगा।

- आशीष मिश्रा, मीडिया प्रभारी, एकेटीयू